**International Journal of Research inSocial Science**
Vol. 11 Issue 12, December 2021,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

# जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और आव्रजन

**डा0 ममता भटनागर**
एसोसिएट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग
विद्यान्त हिन्दू कालेज लखनऊ।

एडमस्मिथ के अनुसार ''कोई भी ऐसा समाज सुखी और सम्पन्न नही रह सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो।''

यह विचार गाँधी के देश के लिए बिल्कुल सटीक है। आजादी के बाद से भारत सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, का मुख्य एजेण्डा विकास के रास्ते पर चलते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है जिससे गरीबी दूर की जा सके और विशाल आबादी का जीवन स्तर ऊँचा किया जा सके। आजादी के बाद के विकास कार्यक्रमों की शुरूआत हमारे के साथ दक्षिण कोरिया व चीन ने भी विकास के कार्यक्रमों को अपनाया था। आरम्भ में यह दोनों देश कुछ श्रेणी में भारत के विकास से पीछे चल रहे थे लेकिन आज दोनों ही हमसे आगे हैं। चीन ने एक विशाल जनसंख्या के साथ विकास के दस प्रतिशत की दर तीन दशकों तक प्राप्त की है लेकिन आज भी हम दस प्रतिशत की विकास दर नही छू पाये है। देश की विशाल आबादी को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए दस प्रतिशत की दर लम्बे समय तक बनाये रखना जरूरी है। भारत की जनसंख्या भारत के लिए एक वरदान के रूप में काम कर सकती है। भारत की भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियां आर्थिक विकास में उपयोगी हो सकती है क्योंकि भारत की 60 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। भारत की औसत आयु 25 वर्ष है जबकि विकसित राष्ट्रों में यह 40 वर्ष का है, औसत आयु कम होने के कारण एक तरफ देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है वही

दूसरी ओर बूढ़े नाबरिक की कम संख्या होने के कारण स्वास्थ्य, पेंशन और देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों पर होने वाला खर्च बेहद कम रह जाता है इसे जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिवीडेड) कहते है लेकिन भारत को इसका फायदा उठाने के लिए युवाओं की शिक्षा में और उनके कौशल विकास करके उनके हाथ में रोजगार देना होगा नही तो यही विकास बेरोजगार युवा की शक्ति अन्य नकारात्मक तरीकों को अपनायेगी जिससे देश के लिए खतरनाक सिद्ध होंगे। विश्व के अन्य देशों ने तेज आर्थिक विकास के सहारे गरीबी और बेरोजगारी में जोरदार कमी की है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा दृश्य नही है। हमारा विकास का माडल समावेशी विकास नही रहा। भारत में 1991 से उदारीकरण के बाद सबसे अधिक लाभ उच्च वर्गो तक ही सीमित रह गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसीलिए सरकार ने 'तेज, स्थाई ज्यादा समावेश विकास का लक्ष्य रखा। हमारे माडल की सबसे बड़ी कमी यही है कि पहले तीव्र विकास का लक्ष्य रखा फिर विकास को समावेशी बनाने का ठीक उसी प्रकार जैसे पहले बच्चे को बड़ा करके बेहतर नागरिक बनाने का कार्यक्रम किया जाये हमने विश्व के देशों से लगभग विपरीत कार्यशैली अपनाई। विश्व के किसी भी देश में ऐसा नही हुआ कि पहले अर्थव्यवस्था को विकसित किया फिर उसका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए विकास के समावेशी बनाने के कार्यक्रम चलाये। हमने अपने युवा जनता के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की सेवाओ में वृद्धि नही की जिससे यह युवा शक्ति प्रशिक्षित श्रमिक व कौशल सहित मानव संसाधन बन पाता।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है उसने 1970 के बाद अर्थव्यवस्था में वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना शुरू किया वही दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारी निवेश किया। व्यावसायिक शिक्षा पर पूरा जोर दिया जिससे चीन की युवा शक्ति

शिक्षित, स्वस्थ और कौशलयुक्त हुई फिर उसने उसे विनिर्माण के क्षेत्रों में खपाना शुरू कर दिया। भारत में यही चूक रह गयी हमने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल को बढ़ावा नही दिया विदेशी निवेशक के आने से 1990 से 2010 तक भारत की विकास दर बढ़ी लेकिन उसका सारा प्रभाव सेवा क्षेत्र में देखने को मिला खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसी कारण विकास का लाभ से गरीबी दूर नही हो सकी। रोजगार के अवसर नही विकसित हुए विनिर्माण क्षेत्र में विश्व में नौकरियाँ बढ़ रही थी परन्तु भारत की विकास दर रोजगार विहीन विकास दर रही। सेवा क्षेत्र में उच्च कौशल की आवश्यकता थी। अतः इसका लाभ शहरों में रहने वाले भारतीयों को मिला विशाल ग्रामीण क्षेत्र की आबादी की स्थिति अधिक खराब हो गयी इसीलिए दो भारत का उदय हुआ। एक शहरी भारत दूसरा ग्रामीण भारत इसमें भी शहरीकरण में उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत अलग–2 नजर आने लगे। नंदन नीलेकेणी ने भी अपनी पुस्तक 'इमेजिनिग इण्डिया' में इसी तरफ संकेत देते हुए कहा कि देश की जननाकीय स्थिति दो कूबड़ वाले ऊँट जैसी है। वर्ष 2025 तक उत्तरी भारत की आबादी बेहद युवा होगी। उसकी औसत आयु 26 वर्ष होगी लेकिन दक्षिण भारत की औसत आयु 34 वर्ष होगी जो यूरोप की 1980 के दशक के अंतिम वर्षो के समान होगी। उत्तरी भारत के चार 'बीमारू' राज्य (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) तथा दक्षिण भारत के चार राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश की तुलना करते है तो उत्तर प्रदेश में 45 करोड़ रहते है तथा दक्षिण में 25 करोड़ की आबादी है दो की तुलना यदि सम्पन्नता में भी करें तो काफी अन्तर है। वर्ष 2011 में प्रति महिला जन्मदर का पूरे भारत में औसत 2.4 है। उत्तर भारत का औसत 3.6 है जबकि दक्षिण भारत का 1.91 है। यह स्पष्ट है कि उत्तरी व दक्षिण भारत का विकास अलग–2 प्रकार से हो रहा है। विदेशी निवेशकों की वृद्धि में

तमिलनाडु प्रशासन तथा कारोबार में अधिक उत्तम है इसका क्या कारण है, स्पष्ट है कि वहां पर जनसंख्या वृद्धि के साथ उनके विकास में शिक्षा व स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर है। अतः गरीबी का स्तर अन्य राज्यों से नीचा है इसी कारण कुछ राज्यों को छोड़कर हमारी जनसंख्या लाभांश देने के स्थान पर हमारे लिए खतरनाक होती जा रही है। उच्च शिक्ष के मापने के लिए वैश्विक स्तर पर सकल नामांन अनुपात का प्रयोग किया जाता है हमारे देश में 12 प्रतिशत (जी.ई.आर.) सकल नामांकन अनुपात है। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण व पिछड़े श्रेणी की स्थिति अत्यन्त खराब है चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक हो या फिर उच्च शिक्षा, शिक्षकों की कमी, स्कूल कालेजों की कमी, महाविद्यालय में सुविधाओं की कमी, निजी क्षेत्र में खुलने वो विद्यालयों के नियंत्रण में कमी, सरकारी नियंत्रण के क्रियान्वयन में कमी जिससे शिक्षा में गुणवत्ता नही आती है। यही स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र में है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति अत्यन्त खराब है, चिकित्सक नही है, दवाईयां नही है, अस्पताल की इमारत नही है, गंभीर बीमारी को छोड़ दे तो सामान्य इलाज के लिए भी चिकित्सा उपलब्ध नही है। सरकारी नियंत्रण कोई नही है, भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजेवाद ने सभी संसाधनों का हरण कर लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढ़ंग से जीवनयापन के लिए आजीविका अवसरों, आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं की कमी की वजह से शहरी क्षेत्रों की ओर से लोगों का पलायन होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वास्तविक व सामाजिक आधारभूत सूविधाओं में काफी अन्तर है। इसी अन्तर के कारण पूर्व राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का एक वृहद मिशन शुरू करके ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरूप को बदलने का विजन उजागर किया था उन्होंने चार सम्पर्क उपलब्ध कराने की बात की थी, वास्तविक सम्पर्क, इलेक्ट्रानिक सम्पर्क, ज्ञान सम्पर्क तथा आर्थिक सम्पर्क।

जिसे 'पुरा' का नाम दिया गया था और इसमें निजी व स्थानीय लोगों` हाथ में प्रबन्धन रहेगा। सरकारी सहायता सही किस्म की प्रबंधकीय संरचना तलाशने के रूप में होगी ताकि ग्रामीण आधारभूत सुविधा का विकास एवं रखरखाव किया जा सके और इसके लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी। आरम्भ में यह योजना सात क्षेत्रों में चलायी गयी। दसवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परन्तु इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को नही मिल सका। क्योंकि प्रबन्धन का कार्य सरकारी तन्त्र के पास था अतः परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई आने लगी।

जनसंख्या वृद्धि से यदि उसके अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास किया जाये तो शहरों की ओर पलायनवाद रूक सकता है इसका उदाहरण गुजरात से देख सकते है गुजरात ने पुरा के कार्यक्रम में सबसे पहले विद्युत उत्पादन को ठीक किया गुजरात के गाँवों में 24 घंटे पूरे वर्ष बिजली रहने से लघु व कुटीर उद्योग गाँव में विकसित हो गये जो हीरे के कारीगर शहरों में रहकर 'हीरे कटिंग' का कार्य करते थे जिसके कारण शहरों में अधिकाधिक जनसंख्या का दबाव था ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आने से हीरे कटिंग का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा। बिजली व इलेक्ट्रानिक सुविधाओं के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा भी जाने लगा तथा शिक्षक भी गाँव में जाने लगा जिससे युवा कौशल का कार्य होने लगा। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण कार्य से यातायात सुगम हो गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ा विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जिन ग्रामीण क्षेत्रों का सम्पर्क पक्की सड़कों से है उन क्षेत्रों में 2000 से 2009 तक आय में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक सड़क निर्माण में 10 लाख का निवेश होता है तो करीब 163 लोग गरीबी के चक्र से बाहर निकल आते है।

प्रो0 आई राजन (ब्मदजतम थ्वत क्मअमसवचउमदज ैजनकपमे ज्ञमतंसं) के अनुसार लगभग 600 मिलियन पलायन है भारत में जबकि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 11.4 मिलियन है। भारत में पलायन के दो प्रकार पाये जाते है। 1. अल्पकालीन पलायन वह है जो रोजगार व शिक्षा के उच्च अवसरों के लिए लोग जाते है इसके कुछ सामाजिक व आर्थिक कारण है भारत में जनसंख्या सबसे अधिक बिहार, उ0 प्र0, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तराखण्ड से पलायन करते है। यलायन करके दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, पंजाब व कर्नाटक में रोजगार व शिक्षा के अवसर खोजते है। पलायनवादी जनसंख्या सबसे अधिक रोजगार पाती है तो निर्माण उद्योग में, घरेलू कार्य, कपड़ा उद्योग, ईट भट्टा उद्योग खनिज व परिवहन में। इसी कारण सामाजिक बुराई भी फैलने लगती है जैसे दिल्ली में रोजगार सबसे अधिक लोग आते। इसी कारण दिल्ली में अपराध बढ़ा है चोरी, चेन खींचना रेप जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई क्योंकि रोजगार सबसे नही मिलता, यदि मिलता है तो सीजनल होता है अतः खाली व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण शहरों में जनसंख्या का बढ़ता दबाव है। इसका कारण है कि जनसुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित नही होना। गुजरात के माडल की बात करे तो श्री मोदी जी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित होने से शहरों की ओर होने वाला पलायन 30 प्रतिशत कम हुआ है। अतः लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना होगा। कृषि घाटे का सौदा हो गई है।

65.5 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है लेकिन भारत दुनियाँ की सबसे अधिक युवा आबादी के बाद भी अशिक्षित, अप्रशिक्षित और कौशलविहीन युवा फौज को लेकर खड़ा 23 दिसम्बर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 7.63 प्रतिशत है। पुरूषों की

दर 13.6 प्रतिशत तथा महिलाओं की 16.1 प्रतिशत है। यह ऊँची बेरोजगारी पलायनवाद का कारण है। यह भीड़ अनौपचारिक क्षेत्रों में काम खोजती है जहाँ पर न तो कोई सामाजिक न, ही आर्थिक सुरक्षा है आज की सबसे बड़ी समस्या अति जनसंख्या का अशिक्षित व बेरोजगार होना है। अगर एक गरीब युवा को उसकी काबिलियत के अनुसार शिक्षा या व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाये तो गरीबी के साथ बेरोजगारी व पलायनवाद को नियंत्रित किया जा सकता है।

**References:**


1. Prof. R. Vaidyanainan – India Useing.
2. Gurcharan Dao – 'India Unbound' from Independence to the Global Transformation Age.
3. IMF – World Economic Outlook – Oct. 2019.
4. National Sample Survey Organisation – NSSO – CSO – Various Survey Reports.
5. Publication Decision of Government of India – India-2020.
6. Kurushatra – 2020 Dec.
7. Newspapers – Business Standard and Navjeevan Kranti.
8. Vimal Jalan-Emerging India
9. Prof.I.Ragan(centre for development studies Kerala)-Articles and Survey reports